

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021

प्रलिस के लयः

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, जकार्ता स्टेटमेंट ।

मेन्स के लयः

पारदर्शता और जवाबदेही, महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, भ्रष्टाचार के कारण और संबंधित उपाय ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' द्वारा ['भ्रष्टाचार बोध सूचकांक' 2021 \(CPI\)](#) जारी किया गया ।

- समग्र तौर पर यह सूचकांक दर्शाता है कि पिछले एक दशक में 86 प्रतिशत देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की स्थिति या तो काफी हद तक स्थिर या खराब रही है ।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन (जर्मनी) में की गई थी ।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु कार्रवाई करना है ।
- इसके प्रकाशनों में वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक शामिल हैं ।

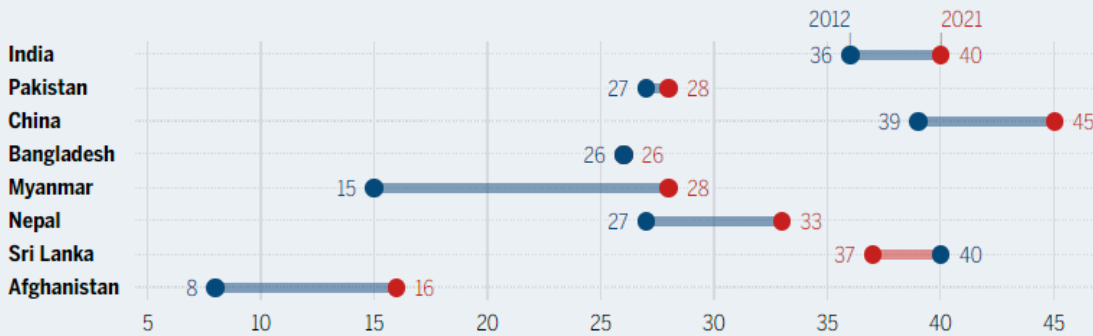
प्रमुख बढि

- परचियः**
 - सूचकांक के तहत कुल 180 देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है ।
 - यह 13 स्वतंत्र डेटा स्रोतों पर निर्भर करता है और इसमें 0 से 100 तक के स्तर का पैटर्न उपयोग किया जाता है, जहाँ 0 का अर्थ सबसे अधिक भ्रष्टाचार है और 100 का अर्थ सबसे कम भ्रष्ट से है ।
 - दो-तर्हई से अधिक देशों (68%) का स्कोर 50 से नीचे रहा है और औसत वैश्विक स्कोर 43 पर स्थिर बना हुआ है । वर्ष 2012 के बाद से अब तक 25 देशों ने अपने स्कोर में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन इसी अवधि में 23 देशों के स्कोर में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है ।
- शीर्ष परदर्शनकर्त्ता:**
 - इस वर्ष शीर्ष देशों में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड शामिल रहे, जिनमें से प्रत्येक को 88 का स्कोर प्राप्त हुआ है । नॉर्वे (85), सांगिपुर (85), स्वीडन (85), स्विट्ज़रलैंड (84), नीदरलैंड (82), लक्ज़मबर्ग (81) और जर्मनी (80) शीर्ष 10 में रहे ।
- खराब परदर्शनकर्त्ता**
 - दक्षिण सूडान (11), सीरिया (13) और सोमालिया (13) सूचकांक में सबसे नचिले स्थान पर रहे ।
 - सशस्त्र संघर्ष या सत्तावाद का सामना करने वाले देश जैसे- वेनेजुएला (14), अफगानिस्तान (16), उत्तर कोरिया (16), यमन (16), इक्वेटोरियल गिनी (17), लीबिया (17) और तुर्कमेनिस्तान (19) आदि को सबसे कम स्कोर प्राप्त हुआ ।
- भारत का परदर्शन:**
 - भारत मौजूदा सूचकांक में 180 देशों में 85वें स्थान (वर्ष 2020 में 86 और वर्ष 2019 में 80) पर है । ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को 40 का CPI स्कोर दिया ।

- भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों को नचिली रैंकिंग मिली है। पाकिस्तान सूचकांक में 16 स्थान गिरकर 140वें स्थान पर पहुँच गया है।
- पछिले एक दशक में भारत का स्कोर काफी हद तक स्थिर रहा है, वहीं कुछ ऐसे तंत्र जो भ्रष्टाचार में मदद कर सकते हैं, कमजोर हो रहे हैं।
- हालाँकि सूचकांक में देश की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई है, क्योंकि भौतिक स्वतंत्रता और संस्थागत नियंत्रण एवं संतुलन का क़षय होता दखि रहा है।
- जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, **मानहानि, देशद्रोह**, अभद्र भाषा और **न्यायालय की अवमानना** के आरोपों व **वदिशी फंडगि संबंधी नियमों** के माध्यम से नशाना बनाया जाता है।

How corruption in India, neighbours changed in 10 years

Perceived levels of public sector corruption on a scale of zero (highly corrupt) to 100 (very clean)



■ लोकतंत्र का पतन:

- **बेलारूस में वपिकषी समर्थकों** के दमन से लेकर नकिरगुआ में मीडिया आउटलेट और नागरिक समाज संगठनों को बंद करने तक **सुझान में परदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हसिा** तथा फालीपीस में मानवाधिकार रक्षकों की हत्या जैसी घटनाओं के कारण दुनिया भर में मानवाधिकार और लोकतंत्र को खतरा है।
- न केवल प्रणालीगत भ्रष्टाचार और कमजोर संस्थानों वाले देशों में बल्कि स्थापित लोकतांत्रिक देशों में भी अधिकारों, नियंत्रण तथा संतुलन में तेज़ी से कमी आ रही है।
 - वर्ष 2012 के बाद से लगभग 90% देशों ने लोकतंत्र सूचकांक पर अपने नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की है।
- वैश्विक **कोविड-19 महामारी** का उपयोग कई देशों में बुनियादी स्वतंत्रता और संतुलन को कम करने के बहाने के रूप में भी किया गया है।
- गुमनाम मुखौटा कंपनियों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिये बढ़ती अंतरराष्ट्रीय गति के बावजूद अपेक्षाकृत **"स्वच्छ"** सार्वजनिक कषेत्रों वाले कई **उच्च स्कोरिंग देश अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार** को जारी रखते हैं।
- सत्तावाद की वर्तमान लहर तख्तापलट और हसिा से नहीं, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने के क्रमिक प्रयासों से प्रेरित है। यह आमतौर पर नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर हमलों, नरिीकषण और चुनाव नकियों की स्वायत्तता को कमजोर करने के प्रयासों तथा मीडिया के नियंत्रण के साथ शुरु होती है।
- इस तरह के हमले भ्रष्ट शासनों को जवाबदेही और आलोचना से बचने की अनुमति देते हैं जिससे भ्रष्टाचार पनपता है।

■ सुझाव:

○ लोगों की मांग:

- भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक पतन के दुषचक्र की समाप्ति हेतु लोगों को नमिनलखिति मांग करनी चाहिये कि उनका सरकारें:
 - सत्ता पर अपनी पकड़ को मज़बूत करने हेतु आवश्यक अधिकारों को बनाए रखना।
 - सत्ता पर संस्थागत जाँच को बहाल तथा मज़बूत करना।
 - भ्रष्टाचार के अंतरराष्ट्रीय रूपों का मुकाबला करना।
 - सरकारी व्यय में 'सूचना के अधिकार' को कायम रखना।

○ मौलिक वफिलताओं को संबोधति करना:

- भ्रष्टाचार वरिधी प्रयासों में एक साथ आगे बढ़ने के लिये **आर्थिक सुधार रणनीतियों की उन मूलभूत वफिलताओं को दूर** करना चाहिये जिनके कारण कई देशों की व्यवस्थाएँ भ्रष्ट हुई हैं।
- भ्रष्टाचार और सामान्य समृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण केवल ज़ागरूक लोगों की भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से इकट्ठा होने, खुले तौर पर बोलने में सकषम हैं।

○ भ्रष्टाचार वरिधी एजेंसियाँ:

- भ्रष्टाचार वरिधी एजेंसी या कमजोर संस्थानों वाले देशों को **भ्रष्टाचार वरिधी एजेंसियों के सिद्धांतों पर वर्ष 2012 के जकार्ता स्टेटमेंट**, कोलंबो कमेंटरी और कषेत्रीय प्रतबिद्धताओं जैसे किटीनविा वज़िन (Teieniwa Vision), **भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** द्वारा आवश्यक अन्य सभी कदमों के साथ बनाए रखा जाना चाहिये।
 - भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार-वरिधी साधन है।

संबंधित भारतीय पहल

- [भारतीय दंड संहिता, 1860](#)
- [भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988](#)
- [धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002](#)
- [वदिशी अंशदान \(वनिियमन\) अधिनियम, 2010](#)
- [कंपनी अधिनियम, 2013](#)
- [लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013](#)
- [केंद्रीय सतरकता आयोग](#)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/corruption-perception-index-2021>

